



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264539  
CG-DL-E-11072025-264539

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3031]  
No. 3031]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3101(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 372 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में गोवा राज्य से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)
“प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय उत्तरी गोवा।	गोवा का पूरा राज्य।”

[फा. सं. सी-18015/9/2025-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 372 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2025

**S.O. 3101(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Bombay at Goa, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 7 relating to the State of Goa, after existing entries in columns (3) and (4), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)
"Court of Principal District and Sessions Judge, North Goa.	The entire State of Goa."

[F. No. C-18015/9/2025-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 372(E) dated the 5th February, 2016.